वर्ष-9 | अंक 05 | 23 सितम्बर से 29 सितम्बर 2024 तक पृष्ठ-12 | MPHIN/2015/63623

न्यूज क्राइम फाइल

आमंत्रण मुल्य 15/-

ग्वालियर, भिंड, मुरैना, छतरपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, सिवनी, जबलपुर, रीवा, सतना, होशंगाबाद, हरदा एवं इंदौर में प्रसारित।

भोपाल झुग्गी मुक्त बनेगा: सीएम

भोपाल को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने के लिए 25 वर्षों का करें प्लान तैयार

उदय प्रताप सिंह चौहान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए समाधाननिकालने के हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि पहले भवन तैयार करने का कार्य हो फिर झुग्गियों को खाली कराया जाये ताकि लोगों को परेशानी न हो। इस महती कार्य में जन-प्रतिनिधियों से भी समन्वय हो। झुग्गी मुक्त करने के लिए अक्टूबर तक निविदा पूरी कर कार्य शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सड़कों के स्वीकृत कार्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो सड़कें अधूरी हैं, उन्हें जल्द पूरा करें। सड़कों की निविदा प्रक्रिया होने के बाद अवार्ड समय पर पारित हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में भोपाल के विकास संबंधी कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने भोपाल शहर को झुग्गी मुक्त करने की तैयारियों की जानकारी भी ली। कलेक्टर भोपाल ने विकास कार्यों संबंधी प्रेजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने के उद्देश्य से आगामी 25 वर्षों के प्लान को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य पूरे किये जायें। भोपाल मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण के प्रस्तावित कार्यों के अंतर्गत रायसेन, मंडीदीप, सलामतपुर और सांची तक का क्षेत्र, राजगढ़ तथा पीलुखेड़ी क्षेत्र, बैरसिया तथा सूखी सेवनिया क्षेत्र के विकास के लिए कार्ययोजना बेहतर ढंग से तैयार की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल शहर सहित जिले के अन्य स्थानों पर फ्लाई-ओवर का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो। भोपाल में बड़े तालाब का स्वरूप प्रभावित हुए बगैर एलिवेटेड कॉरिडोर का प्लान तैयार करें। सीएम राइज स्कूलों का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पतालों के भवन निर्माण समय पर किये जाये। अृमत योजना के कार्यों को निर्धारित कार्ययोजना के तहत पूरा करें। आदमपुर बायो-सीएनजी प्लांट का कार्य और कचरे का निष्पादन आधुनिक तकनीक से पूरा हो। जिले में सीवेज, जल व तालाबों का पुनरोत्थान कार्य के लिए लगभग 1522 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिली है।

सरकारी भवनों में सोलर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकारी भवनों में सोलर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करें। इस संबंध में अभियान चलाकर भोपाल को आदर्श बनायें। लोगों को प्रेरित किया जाएं, जिससे घरों की छतों पर सोलर पैनल अधिक संख्या में लग सकें। मेट्रो रेल परियोजना के कार्य चरणबद्ध ढंग से पूरे किये जायें। उन्होंने वंदे मेट्रो का प्लान भी तैयार करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस विभाग की आवश्यकताओं के लिए समग्र प्लान बनायें। राजधानी को विकसित करने और ट्रैफिक का प्लान भी बेहतर रूप से बनाया जाये। हाउसिंग बोर्ड, भोपाल विकास प्राधिकरण और स्मार्ट सिटी द्वारा भोपाल के विकास के लिए 25 साल का प्लान तैयार किया जाये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि उद्योगों और रोजगार के लिए प्रभावी कार्य हो और नीति निवेश के लिए अन्य राज्यों का अध्ययन भी किया जाये।

सड़कों के विकास कार्य

बैठक में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग (कोलार) का निर्माण कार्य 305 करोड़ रुपए की राशि से अक्टूबर 2024 तक पूर्ण करना है। इसका 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कलियासोत डेम से न्यू बायपास मार्ग का कार्य 49. 50 करोड़ रुपए से अक्टूबर 2024 तक पूर्ण किया जाना है, जिसका 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। भोपाल शहर में 42 करोड़ रूपये की लागत से भदभदा-बिलकिसगंज रोड दिसम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना है, जिसकी लंबाई 6 से 13 कि.मी. तक है। इस रोड का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। पिपलानी बी-सेक्टर खजूरीकलां होते हुए नया बायपास तक फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य 25.44 करोड़ रुपए में मार्च 2025 तक पूर्ण होना है, जिसका 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी तरह भोपाल चिकलोद मार्ग पर 11 मील चौराहे से बंगरसिया तक 2 लेन से 4 लेन करने का उन्नयन कार्य 49 करोड़ रुपए से दिसम्बर 2025 तक पूर्ण होना है, जिसका 0.50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। इसी तरह सीपीए-2 विभाग के तहत एम.जी.एम. स्कूल से बायपास को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण 9.39 करोड़ रुपए में दिसम्बर 2025 तक पूर्ण होना है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

गढ़ाकोटा के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में दशलक्षण पर्व के समापन अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित क्षमावाणी समारोह में सम्मिलित होकर धर्मसभा को संबोधित किया!!
गोपाल भार्गव -विधायक रहली, पूर्व मंत्री

भोपाल में एक और मासूम से ज्यादती की सूचना

5 साल की बच्ची मां से रोते हुए बोली-स्कूल वैन में अंकल ने की गलत हरकत

भोपाल ब्यूरो

भोपाल में 5 साल की बच्ची से रेप का सूचना पुलिस को मिली है। स्कूल से घर पहुंची बच्ची ने मां से कहा कि स्कूल वैन वाले अंकल दूसरे बच्चों को छोड़ने गए थे तब किसी दूसरे अंकल ने गलत हरकत की। परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। बच्ची ऐशबाग इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में केजी (किंडरगार्डन) क्लास में पढ़ती है। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल डीसीपी रश्मि अग्रवाल भी मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटनास्थल के पास एक दुकान के सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर जब्त किए गए हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। बता दें कि राजधानी में चार दिन में मासूम बच्ची से ज्यादती का ये दूसरा मामला है। इससे पहले कमला नगर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल के वॉशरूम में आईटी टीचर ने तीन साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया था।

रोते हुए घर पहुंची थी बच्ची

बच्ची ऐशबाग के एक मोहल्ले की रहने वाली है। वैन से स्कूल आती-जाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद शनिवार को वैन से घर आ रही थी। ड्राइवर ने श्री प्रोविजन स्टोर के सामने वैन पार्क की। इसके बाद कुछ बच्चों को उतारकर उन्हें उनके घर तक छोड़ने गया। वह करीब 5 मिनट बाद लौटा और फिर बच्ची को उसके घर ड्रॉप किया। घर में बच्ची रोते हुए पहुंची। मां के पूछने पर उसने बताया कि एक अंकल ने उसके साथ वैन में गंदी हरकत की।

पुलिस ने दुकानों के सीसीटीवी डीवीआर किए जब्त

पुलिस ने प्रोविजन स्टोर में लगे डीवीआर जब्त कर लिए हैं। स्टोर के बगल में ही एक कबाड़ा दुकान के फुटेज भी टीआई जितेंद्र गढ़वाल और स्टाफ ने चेक किए।

एसीपी ने कहा- परिजन थाने आए

एसीपी सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि बच्ची के परिजन कुछ कनफ्युजन के साथ थाने आए थे। जिसकी तस्दीक की गई। फिलहाल, बच्ची के साथ किसी तरह के गलत काम की पुष्टि नहीं हुई है।

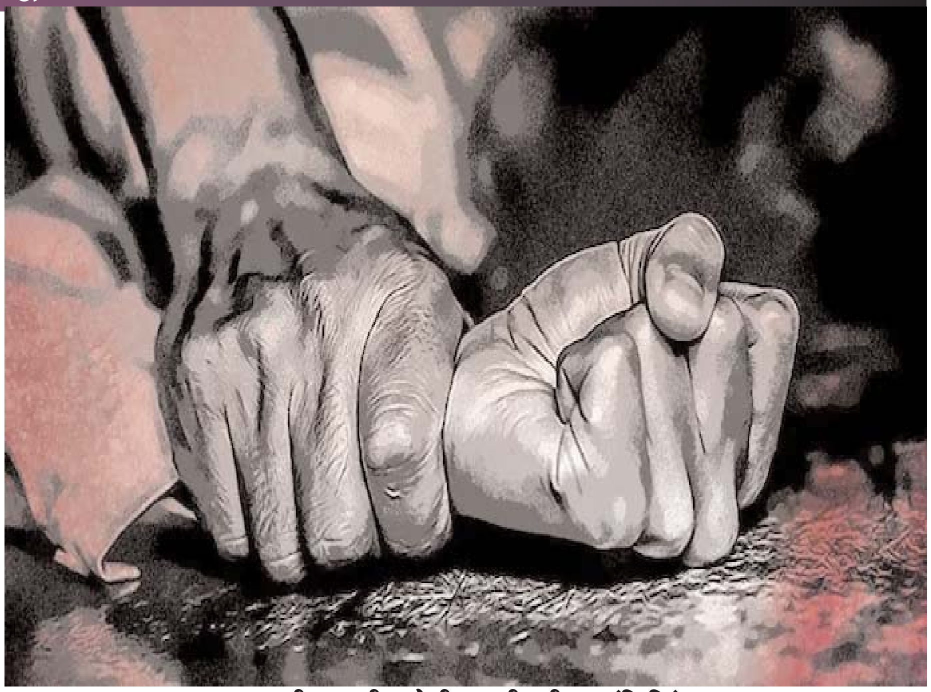

सीडब्लूसी करेगी बच्ची की काउंसिलिंग

डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि छोटे बच्चे घटनास्थल को लेकर कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। लिहाजा मामले की तस्दीक कराई जा रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्लूसी) के एक्सपर्ट्स से रविवार को बच्ची की काउंसिलिंग कराएंगे। बच्ची ने शिकायत की थी कि अंकल (वैन ड्राइवर) दूसरे बच्चों को छोड़ने के लिए वैन पार्क कर गए थे। इसी बीच एक और अंकल आए और गलत तरह से टच किया। हालांकि, वैन में सवार दूसरे बच्चों ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है।

युवक ने सुसाइड नोट छोड़कर फांसी लगाई

मां से माफी मांगी, अर्थी के साथ मोबाइल जलाने की बात लिखी

न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल के कोलार इलाके में रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस को उसके पास से सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उसने लिखा कि मां मुझे माफ कर देना। मैने आपको बहुत परेशान किया। मेरे मोबाइल फोन को मेरी अर्थी के साथ ही जला देना। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बड़े भाई से निवेदन है कि मेरी मां का बहुत खयाल रखना। आपका छोटा भाई, मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना शुक्रवार की शाम की है। पीएम के बाद शनिवार को बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। धनराज अहिरवार (19) पुत्र स्वर्गीय शिवराम अहिरवार निवासी सी सेक्टर सूर्य कॉलोनी पांचवी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ चुका था। फिलहाल कोई काम नहीं करता था। धनराज के भाई नारायण अहिरवार ने बताया कि बहन और मां घरों में काम करती हैं। शुक्रवार को दोनों काम पर गई थीं। वह अलग रहते हैं और प्राइवेट जॉब करते हैं। पिता की बीमारी के चलते 6 साल पहले मौत हो चुकी है। घटना के समय भाई घर में अकेला था। तभी उसने फांसी लगा ली। उसकी मौत

की सूचना पड़ोसियों ने दी थी। तब बहन और मां फिर मैं मौके पर पहुंचा था।

महिला से बात करने पर मां लेती थी आपत्ति

नारायण का कहना है कि धनराज की एक विवाहित महिला से दोस्ती थी। वह उससे फोन पर बेहद बातचीत करता था। उसके घर भी आना जाना था। इस बात पर मां को एजराज था। इससे नाराज होकर मां उसे फटकार लगाती थी। जिससे वह नाराज हो जाया करता था। शुक्रवार को हमसे पहले सुसाइड की सूचना मोहल्ले में रहने वाली इसी महिला को मिली। उसने परिजनों के साथ घर आकर भाई के शव को फंदे से उतार दिया था। जब हम घर पहुंचे तो शव जमीन पर मिला। भाई ने पेंट की जेब में सुसाइड नोट छोड़ा है, इसमे मोबाइल को अर्थी के साथ जला देने की बात लिखी है।

घर से परेशान था युवक

केस की जांच कर रहे एएसआई संतोष कुमार ने बताया कि युवक ने घर से परेशान होकर खुदकुशी की है। मां व अन्य परिजन उसे काम करने के लिए बोलते थे। इस बात से वह नाराज हो जाया करता था। शुरुआती जांच में इसी तनाव में आने के बाद उसके द्वारा सुसाइड की बात सामने आ रही है। परिजनों के डिटेल बयान अभी दर्ज नहीं किए जा सके हैं।

रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस की सभी वीर जवानों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! रेलवे की सुरक्षा हेतु आपकी अविचल दृढ़ता, निरंतर सतर्कता एवं समर्पण सराहनीय है।
योगी आदित्यनाथ- मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश

बीजेपी सांसद ने की 110 पटवारी-आरआई को हटाने की मांग

भोपाल में कलेक्टर को सौंपी लिस्ट; कहा- इनकी वजह से बदनामी हो रही

न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल में सालों से कई (राजस्व निरीक्षक) और पटवारी एक ही हल्के में 8 से 15 साल से जमे हैं। इनके कारण ऑफिस बदनाम होता है। उनकी शिकायतें भी मिलती हैं। उन्हें वल्लभ भवन के आला अफसरों का संरक्षण है। कइयों की जमीन है। उन्हें हटाने के लिए लिस्ट सौंपी है। यह कहना है भोपाल सांसद आलोक शर्मा का। उन्होंने प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप के सामने भी यह मुद्दा उठाया है। साथ ही कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को लिस्ट दी है। इसके बाद प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। दरअसल, सांसद ने कई आरआई और पटवारियों को वल्लभ भवन के सीनियर अफसरों का संरक्षण होने का आरोप लगाया है।

3 साल में हल्का बदलने का नियम

भोपाल में करीब 190 पटवारी हैं। वहीं, राजस्व निरीक्षकों की संख्या लगभग 35 है। नियमानुसार 3 साल में पटवारी का हल्का बदल देना चाहिए। लेकिन भोपाल में कई तो 8 साल या इससे ज्यादा समय से पदस्थ हैं। बताया जाता है कि कई पटवारियों की शिकायत भी जनप्रतिनिधियों तक पहुंची। यही वजह है कि सांसद शर्मा को प्रभारी मंत्री के सामने यह मुद्दा उठाना पड़ा।

अवैध कॉलोनी का मुद्दा भी उठाया, बोले-ड्राइवर-प्यून के नाम ले रहे जमीन

भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप के सामने कलेक्टर को पटवारी और राजस्व निरीक्षकों की शिकायत की।

सांसद शर्मा ने अवैध कॉलोनी और शहर के ट्रैफिक का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में अवैध कॉलोनियों के संबंध में जल्द ही बड़ी बैठक करेंगे। जो लोग अवैध कॉलोनी काट रहे हैं और जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। कई कॉलोनाइजर अपने ड्राइवर और प्यून के नाम से जमीन ले लेते हैं। इससे वे बच जाते हैं। ऐसे मामलों की जांच भी कराएंगे।

मैं कलेक्टर बोल रहा हूं...मेरे नंबर पर रुपए भेज दो

भोपाल कलेक्टर के नाम पर फर्जी कॉल; संबल स्कीम का फायदा देने का झांसा

न्यूज क्राइम फाइल

मैं कलेक्टर बोल रहा हूं... संबल स्कीम का फायदा चाहिए तो मेरे इस नंबर पर रुपए भेज दें।

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के नाम पर कुछ इसी तरह से जालसाज ग्रामीणों से ठगी कर रहे हैं। ठगों ने कलेक्टर की फोटो की फर्जी आईडी बनाई। ताकि, लोगों को लगे कि वह सही में कलेक्टर ही हैं। इसके बाद ठग संबल योजना की राशि डालने के नाम पर 3 हजार से 10 हजार रुपए तक की मांग कर रहे हैं। खास बात ये है कि भोपाल के फंदा जनपद क्षेत्र में ही 2-3 लोगों ने 10 हजार रुपए अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए। मामला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के पास भी पहुंचा। जिसके बाद क्राइम ब्रांच इसकी जांच में जुट गई है।

फंदा जनपद के ही 15-20 लोगों को कॉल-मैसेज

पिछले एक सप्ताह से कलेक्टर की फर्जी आईडी से फंदा

जनपद क्षेत्र के लोगों को कॉल के साथ मैसेज किए जा रहे हैं।

जनपद के एक कर्मचारी ने बताया कि हितग्राहियों को कॉल के अलावा मैसेज भी किए जा रहे हैं। मैसेज में कलेक्टर की फोटो लगी है। इसलिए लोगों ने ठग को सही में कलेक्टर मानकर रुपए भेज दिए। फंदा के अलावा बैरसिया जनपद क्षेत्र में भी फर्जी कॉल पहुंचे हैं। करीब 15 से 20 लोगों से ठगी की जा चुकी हैं।

ऐसे हो सका मामले का खुलासा

कलेक्टर की फोटो लगी फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने के मामले का खुलासा जब हुआ तो जनपद स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों को मैसेज किए गए हैं। जिसमें लिखा है- सभी सचिव एवं जीआरएस मेरे भेजे गए इन नंबरों को देख लें, यह फर्जी आईडी से संबल योजना की राशि डालने के लिए फोन करता है। कृपया कोई भी इस पर ध्यान न दें। तत्काल रिपोर्ट करने को कहें या पास के थाने में रिपोर्ट करें। किसी भी परिस्थिति में कोई राशि न डालें। यह कलेक्टर के नाम से फर्जी फोन करता है।

कलेक्टर ने कहा- तुरंत करें इसकी शिकायत

कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने बताया कि यह फर्जी आईडी है। कोई भी मेरे नाम से रुपयों की मांग करता है तो तत्काल शिकायत करें। रुपए कतई न दें। पात्र हितग्राहियों को संबल समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कोई अन्य भी राशि की मांग करता है तो तुरंत शिकायत करें।

पूज्य पिताजी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर आज भोपाल निवास पर श्रद्धांजलि एवं भजन संध्या का आयोजन किया।
प्रदेश अध्यक्ष - भाजपा मध्यप्रदेश

आलेख

तिरुपति में प्रसादम से खिलवाड़

आस्था पर आघात

ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

लाखों-करोड़ों हिन्दू श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र तिरुमाला भगवान वेंकटेश्वरस्वामी मंदिर में मिलने वाले लड्डू वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल की शर्मनाक एवं लज्जाजनक घटना ने न केवल चौंकाया है बल्कि मन्दिर व्यवस्था पर सवाल खड़े किये हैं। यह मामला जितना सनसनीखेज है, उतना ही आस्था पर आघात करने वाला भी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पहले यह कहा कि तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं को बनाने में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें पशुओं की चर्बी मिली रहती थी, फिर उन्होंने गुजरात की एक सरकारी प्रयोगशाला से मिली रपट के आधार यह कहा कि लड्डुओं को बनाने में जिस घी का उपयोग होता था, उसमें सचमुच पशुओं की चर्बी, मछली के तेल आदि का प्रयोग होता था। यह घटना हिन्दू आस्था, पवित्रता एवं मन्दिर संस्कृति को धुंधलाने की कुचेष्टा एवं एक विडम्बनापूर्ण त्रासदी है। अगर प्रसाद के मिलावटी एवं अपवित्र होने की बात सही है तो इससे अधिक आघातकारी, अनैतिक एवं अधार्मिक और कुछ हो ही नहीं सकता। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रसाद के तौर इन लड्डुओं का वितरण न केवल श्रद्धालुओं के बीच किया गया, बल्कि भगवान को भी भोग के तौर पर यही लड्डू चढ़ाया जाता था। अब इस मामले में केंद्र सरकार एवं प्रांत सरकार के दखल देने मात्र से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता क्योंकि हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाला यह प्रकरण अक्षम्य अपराध है, जिसकी गहन जांच होनी ही चाहिए, ताकि ऐसे जघन्य कृत्य अन्य मन्दिरों की अस्मिता के धुंधलाने के कारण न बने। प्रथम दृष्ट्या मंदिर प्रबंधन प्रसादम से खिलवाड़ का दोषी है। जो मंदिर प्रतिदिन तीन लाख लड्डू बेचकर सालाना 500 करोड़ रुपये तक लाभ कमाता है, वह क्या इतना सक्षम नहीं कि गुणवत्ता जांच के लिए एक किफायती प्रयोगशाला ही बना ले? मंदिर प्रबंधन के पास न तो अपनी जांच सुविधाएं हैं और न वह जांच कराने का इच्छुक था? देश के संपन्नतम मंदिरों में शुमार यह तीर्थ अगर गुणवत्ता, आस्था एवं पवित्रता से समझौता कर रहा है, तो देश के बाकी मंदिरों में क्या हो रहा होगा, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। मन्दिरों एवं आस्थास्थलों पर दिनोंदिन बढ़ रही श्रद्धालुओं की आस्था एवं भीड़ से आर्थिक लाभ कमाने की मानसिकता न केवल घिनौनी है बल्कि शर्मनाक भी है। मंदिर तो भगवान भरोसे चल रहे हैं, पर मन्दिर-प्रबंधन स्वयं को अर्थपति बनाने में जुटा है, यही कारण है कि मन्दिर को धंधा बना दिया गया है, ऐसे मन्दिर प्रबंधकों, पूजारियों एवं पदाधिकारियों की श्रद्धा न तो भगवान के प्रति है और न भक्तों के प्रति। वे तमाम मंदिर, जो अपने यहां से प्रसाद वितरित करते हैं या बेचते हैं, उन सभी को गुणवत्ता, शुद्धता एवं पवित्रता जांच की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। एक बड़ा सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं, जिन्हें पवित्रता एवं जन-आस्था की परवाह नहीं है। मंदिर ट्रस्ट ने प्रसादम से खिलवाड़ और मिलावट की पुष्टि की है। देश के एक पवित्रम श्रद्धा केंद्र तिरुपति मंदिर का प्रबंधन करने वाली संस्था तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कहा है कि घी के आपूर्तिकर्ताओं ने मंदिर में गुणवत्ता जांच की सुविधा न होने का फायदा उठाया है। अब सवाल उठता है कि मंदिर प्रबंधन की सफाई या स्वीकारोक्ति को कितनी गंभीरता से लिया जाए? क्या मंदिर प्रबंधन को अपराध की गंभीरता का अंदाजा है? क्या मंदिर प्रबंधन को मंदिर की पवित्रता का अनुमान है? देश एवं दुनिया के सबसे चर्चित आस्थास्थल से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। यह अफसोस की बात है कि मंदिरों में बाहर से चढ़ने वाला प्रसाद तो पहले से ही संदेह के दायरे में रहता है, पर अगर मंदिर की अपनी रसोई में तैयार होने वाले प्रसाद की भी विश्वसनीयता आहत हुई है, तो यकीन मानिए, इंसान फिर किन पर भरोसा करेगा? क्योंकि व्यापार में मिलावट तो चल ही रही है, अब मन्दिरों में यानी भगवान के दरबार में मिलावट से मनुष्यता गहरे रसातल में चली गयी है। मूल्यहीनता एवं अनैतिकता की यह चरम पराकाष्ठा है। गुणवत्ता एवं पवित्रता सुनिश्चित करने वाले अधिकारियों के लिए यह एक गंभीर चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। इस खुलासे के बाद लोग अपना गुस्सा एवं आक्रोश भी जाहिर कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही 1984 में भी हुआ था जब डालडा में चर्बी मिले होने का मामला सामने आया था, लेकिन वह व्यापार का मामला था, लेकिन तिरुपति प्रसादम में मिलावट का मामला आस्था का है। भूल, अपराध एवं लापरवाही की नब्ज को ठीक-ठीक समझना जरूरी है। भूल सही जा सकती है, लेकिन लापरवाही एवं आपराधिक सोच को सहन नहीं किया जा सकता। दरवाजे पर बैठा पहरेदार भीतर-बाहर आने-जाने वाले लोगों को पहचानने में भूल कर सकता है मगर सपने नहीं देख सकता। लापरवाही एवं अपराधिक मानसिकता विश्वसनीयता एवं पवित्रता को तार-तार कर देती है। बुराइयां जब भी मन पर हावी होती हैं, गलत रास्ते खुलते चले जाते हैं। मन्दिरों पर बुराइयां हावी होना चिन्ताजनक ही नहीं, गंभीर खतरों के संकेत हैं। मन्दिर प्रबंधन को अधिक चुस्त-दुरस्त, पारदर्शी एवं नैतिक बनाने की भी जरूरत है। प्रश्न है कि हिन्दू मन्दिरों में ही ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं, क्या मन्दिर प्रबंधन अन्य समुदायों के मन्दिरों या धार्मिक-स्थलों की तरह पवित्र, गुणवत्ता पूर्ण, उच्च चारित्रिक एवं नैतिक देखभाल नहीं कर सकते? यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने लोगों को कलियुग के कष्टों और परेशानियों से बचाने के लिए अवतार लिया था। यहां बालों का दान किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने मन से सभी पाप और बुराइयों को यहां छोड़ जाता है।

संपादकीय

सिर्फ कानून बनाने से नहीं रुकेंगे महिला अपराध

देश के नेताओं ने समस्याओं का आसान रास्ता तलाश कर रखा है। जब भी किसी समस्या से सामना हो तो कानून बना कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। समस्या की जड़ तक कोई भी राजनीतिक दल और सरकारें नहीं जाना चाहती। ऐसा नहीं है कि समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता, किन्तु वहां तक पहुंचने और व्यवहारिक समाधान ढूंढने में पापड़ बेलने पड़ते हैं। पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने महिला चिकित्सक से बलात्कार के बाद हत्या के मामले में वही किया है जो अब तक ऐसे मामलों में दूसरे राज्य या केंद्र सरकार करती रही हैं। मसलन कानून बना कर जिम्मेदारी पूरी कर ली। ममता सरकार ने विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए, और उन्हें पेरोल की सुविधा न दी जाए। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024% शीर्षक वाले इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नये प्रावधानों के जरिये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है। यह बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, उनसे पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। इससे पहले 2019 में आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक और 2020 में महाराष्ट्र शक्ति विधेयक विधानसभा से पारित हुआ था। इन दोनों विधेयकों में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के सभी तरह के मामलों में अनिवार्य फांसी का प्रावधान किया गया था। इन दोनों विधेयकों को राज्य विधानसभाओं ने सर्वसम्मति से पारित किया था। लेकिन दोनों विधेयकों अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ-साथ 2012 के पोक्सो अधिनियम के कुछ हिस्सों में संशोधन करने और पीड़िता की उम्र चाहे जो हो, कई तरह के यौन उत्पीड़न के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है। इस बिल में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

कश्मीर के बडगाम में सीमा सुरक्षा बल के वाहन के खाई में गिरने से 3 जवानों के शहीद होने की खबर से अत्यंत दुःख हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।
जीतू पटवारी अध्यक्ष, मप्र कांग्रेस

बच्ची से रेप का आरोपी अब बंदी नंबर-3075

जिस बाइकर ग्रुप का मेंबर था, उसने भी की फांसी की मांग; एसआईटी ने परिवार से पूछताछ की

न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल में कमला नगर स्थित प्राइवेट स्कूल में 3 साल की मासूम से रेप का आरोपी कासिम रेहान जेल में है। उसे बंदी नंबर 3075 के रूप में हॉल नंबर 17 में रखा गया है। यहां उसके साथ 86 अन्य कैदी हैं। जेल जाने के बाद से ही कासिम गुमसुम है। बुधवार शाम से गुरुवार दोपहर तक उसने कुछ नहीं खाया था। इसके बाद जेल अधिकारियों ने बात की, तब कासिम ने गुरुवार रात का खाना खाया। इधर, SIT की कोशिश है कि जल्द से जल्द मामले की चार्जशीट पेश की जाए। विशेष जांच रही शुक्रवार दोपहर को कासिम के बैरसिया रोड पर जिया कॉलोनी स्थित घर पहुंची। इस टीम के साथ कमला नगर और निशातपुरा थाने के करीब 15 पुलिसकर्मी शामिल थे। यहां कासिम के परिजन के बयान दर्ज किए गए हैं। उसके आचरण को लेकर पूछताछ की गई है। वहीं, कासिम जिस बाइकर ग्रुप के साथ जुड़ा है, उसी ग्रुप ने प्रदर्शन करते हुए कासिम को फांसी दिए जाने की मांग की है।

5 साल पहले लव मैरिज की, बीवी से अलगाव

स्कूल में जॉब से पहले आरोपी कासिम एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। कंपनी के साथ काम के सिलसिले में करीब 6 साल पहले वह लखनऊ गया था। यहां एक युवती के सपंर्क में आया। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और पांच साल पहले लव कम अरेंज की। हालांकि उसकी बीवी बीते कई महीनों से सेपरेट है। दोनों की कोई संतान नहीं है।

कम्प्यूटर हार्डवेयर में डिप्लोमा होल्डर है कासिम

कासिम कॉर्मस ग्रेजुएट है। इसके बाद उसने कम्प्यूटर हार्डवेयर में डिप्लोमा किया। स्कूल में कम्प्यूटर से जुड़ी टेक्निकल समस्याओं को हल करने के लिए उसे हायर किया गया था। स्कूल परिसर में उसका आईटी रूम बना हुआ है। इसी में बैठकर कसिम काम किया करता था।

बच्ची ने कॉन्स्टेबल मां को बताया- वॉशरूम में बैड टच किया

आरोपी कासिम ने पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर लिया है। वह कई दिनों से यौन शोषण कर रहा था। घर पर बच्ची की कॉन्स्टेबल मां ने खरोंच देखी तो मामला खुला। बच्ची की मां ने बताया- रोज की तरह 3 साल की बेटी 13 सितंबर को स्कूल से आई। रात करीब 11 बजे मैंने देखा तो कि उसके प्राइवेट पार्ट में खरोंच के निशान हैं। पहले मुझे लगा कि खुद से हुआ होगा, लेकिन बाद में खरोंच बढ़ी तो बेटी से पूछा- बेटा कोई आपको बेड टच करता है क्या? बेटी कुछ ज्यादा नहीं बता पाई पर इतना कहा कि स्कूल के एक अंकल वॉश रूम में बैड टच करते हैं। मैं

बेटी को लेकर थाने पहुंची। मेडिकल में पता चला कि बेटी से छेड़छाड़ की गई है। स्कूल पहुंचे तो उसने आईटी टीचर को पहचान लिया। इसके बाद सीडब्ल्यूसी ने काउंसिलिंग की। तब पूरा मामला खुला।

पत्रकार बनने का सुनहरा अवसर

अगर आपके अंदर लिखने का कौशल है और पत्रकारिता में रुचि है, तो 'न्यूज क्राइम फाइल' को आपकी तलाश है। 'न्यूज क्राइम फाइल' से जुड़ कर आप हर माह दस हजार रुपये तक कमा सकते हैं। 'न्यूज क्राइम फाइल' भोपाल, ग्वालियर, सतना, सागर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और नीमच में ब्यूरो ऑफिस खोलने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार तत्काल हमें अपना बॉयोडाटा मेल करें या व्हाट्सअप करें।

उदय प्रताप सिंह चौहान (संपादक) 07223003441
संजीव कुमार (ब्यूरो प्रभारी भोपाल) 08224965455
email: newscrimefile@yahoo.com

कोलकाता में उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात के दौरान सभी सेक्टर में चर्चा हुई है, जिसमें लगभग रू.20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं।
मोहन यादव- सीएम मप्र

तिरुपति लड्डू विवाद, धीरन्द्र शास्त्री बोले- ये सनातन के खिलाफ साजिश

दोषियों को फांसी की मांग; शंकराचार्य ने कहा-मंदिरों में सरकारी दखल खत्म हो

न्यूज क्राइम फाइल

आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (तिरुपति मंदिर) के प्रसाद लड्डुओं को जिस घी से बनाया जा रहा था, उसमें जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि के बाद देशभर में इस पर कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा- जैसा दावा किया जा रहा है, अगर ये सत्य है तो यह बहुत बड़ा अपराध है। उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने भी कहा कि यह भक्तों की भावनाओं के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ और अपराध है। भगवान के प्रसाद में अपवित्र घटक मिलाना समस्त हिंदू जन समुदाय के प्रति अपराध है। इस मामले पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच होना चाहिए और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर सख्त सजा देनी चाहिए।

धीरेन्द्र शास्त्री ने बोले- ये सनातनियों के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शुक्रवार रात को बागेश्वर धाम में प्रवचन के दौरान कहा- यह निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है। इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों का

धर्म भ्रष्ट करने की पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा दे। उन्होंने कहा- अगर भगवान के प्रसाद में चर्बी या मछली के तेल का प्रयोग किया गया हैं, तो इससे बड़ा वर्तमान में भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसकी बारीकी से जांच होना चाहिए।

सरकार को हिंदुओं के मंदिरों को हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए

पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सरकार को शीघ्र अति शीघ्र हिंदुओं के मंदिरों को हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वहां पर बारीकी से सभी सनातनी जांच करवाएं और दोबारा इस प्रकार की यह घटना न हो इसके लिए सभी एकजुट होकर तैयार रहें।

कमलनाथ बोले- प्रसाद मामले में पूरी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शनिवार को खजुराहो पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम ने बालाजी के प्रसाद मामले में कहा कि बड़े दुख की बात है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, इस प्रक्रिया का खुलासा होना चाहिए।

शंकराचार्य बोले- यह अपराध किसी की हत्या करने से भी बड़ा अपराध

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा- यह अपराध किसी की हत्या करने से भी बड़ा अपराध है। दंड ऐसा मिलना चाहिए कि भविष्य में ऐसा किसी और मंदिर में न हो सके। देश के सभी मंदिरों के प्रबंधन से सरकार का हस्तक्षेप पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। क्योंकि मंदिरों में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वहन केवल संस्कृति से जुड़े लोग ही कर सकते हैं।

मंदिरों की पूजा पद्धति में सरकार का नियंत्रण खत्म होना चाहिए

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा- मंदिरों की पूजा पद्धति में सरकार का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए। मंदिरों का प्रबंधन धर्माचार्यों के हाथों में दिया जाना चाहिए, ताकि मंदिरों की परंपरा और संस्कृति को बचाया जा सके। शंकराचार्य ने कहा कि तिरुमला मंदिर में जो हुआ है, वही बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में हो रहा है। यहां भी सरकार पारंपरिक लोगों को हटाकर अब सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है। ऐसे में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ होना सामान्य बात हो जाएगी, क्योंकि जो लोग मंदिरों में काम करेंगे वह आस्था से नहीं बल्कि नौकरी से करेंगे।

तिरुपति के प्रसाद पर बोले- पता नहीं कितनी बार चर्बी खाई होगी

तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा- यह दुर्भाग्य की बात है, लोग इस तरह से सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करें तो यह बहुत ही दुख की बात है। लोगों का धर्म भ्रष्ट करना, जैसे मैं खुद ही जब यह खबर देखी तो भोजन नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने कई बार वहां का प्रसाद खाया है, मुझे लगा कि पता नहीं मैंने कौन सी चीज खाई है, मन में एक ग्लानि सी है और गुस्सा भी है। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है।

कांग्रेस का फिर कलेक्टरों पर जुबानी हमला

सिंघार ने कहा- बीजेपी, आरएसएस का झंडा उठाने का शौक है तो आरएसएस की चड्डी पहनो

न्यूज क्राइम फाइल

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किसान न्याय यात्रा के दौरान बीजेपी और आरएसएस की तरफदारी करने वाले कलेक्टरों और अधिकारियों को घेरा है। अलीराजपुर में न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए सिंघार ने कहा है कि किसी अधिकारी को, किसी कलेक्टर को बीजेपी और आरएसएस का झंडा उठाने का ज्यादा ही शौक है तो आरएसएस की चड्डी पहनो, शाखा में जाओ, यहां कलेक्टरी की जरूरत नहीं है। आपको, आम जनता के लिए सेवा करना पड़ेगी। यह मैं यहां के कलेक्टर को कहना चाह रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में दलाली होती रही, इसलिए इन्हें यही दिखाई देता है। दरअसल कांग्रेस ने कल पूरे प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकालकर बीजेपी सरकार से किसानों के हित में किए गए वादों को पूरे करने और अधूरे वादों पर सरकार को घेरने के लिए आंदोलन किया था। इस यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष सिंघार द्वारा अलीराजपुर कलेक्टर पर किए गए हमले का वीडियो अब सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि कलेक्टर को ज्यादा ही बीजेपी और आरएसएस का झंडा

उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष | वीडी शर्मा, अध्यक्ष, भाजपा

पकड़ने का शौक है तो आरएसएस की चड्डी पहनकर शाखा में जाएं और कलेक्टरी छोड़ें। सिंघार ने यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ट्वीट भी किया है।

किसान न्याय यात्रा पर कहा, धोखे से कांग्रेस सरकार बनी तो किसानों को भूल गए

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस भूल गई कि पंद्रह माह की सरकार में किसानों के साथ वादाखिलाफी कांग्रेस ने की थी। धोखे से सरकार बन गई तो किसानों को भूल गए। किसानों को धोखा दिया। जब सरकार गिर गई तो किसानों से बीजेपी को मौका दिया। पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य किसानों को सक्षम बनाना है। प्रदेश में तो किसानों के लिए सरकार एक पैर पर खड़ी रहती है। किसान तो बीजेपी की ताकत हैं।

कांग्रेस में दलाली होती रही है, इसलिए इन्हें यही दिखाई देता है

शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस इसी तरह के भाव से काम करती रही है। उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दलाल दिग्विजय सिंह को बताया था, शराब माफिया बताया था। कांग्रेस की सरकार में दलाली होती रही, इसलिए इन्हें यही दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की संवेदनशील सरकार मध्य प्रदेश में है। उमंग सिंघार अपने कार्य व्यवहार में भी ध्यान रखें। शर्मा ने कहा कि कोई भी गलत काम करेगा तो कार्रवाई होगी।

वर्धा के कार्यक्रम में महाप्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा खरीदने का सौभाग्य मिला। उनसे प्रार्थना है कि वे सभी देशवासियों को स्वस्थ और सानंद रखें।
प्रधानमंत्री- नरेंद्र मोदी

आईपीएल ऑक्शन नवंबर में विदेश में होने की संभावना

टीमों के रिटेंशन नियमों का इंतजार; राजस्थान रॉयल्स से जुड़ सकते हैं विक्रम राठौर

न्यूज क्राइम फाइल

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 18वें सीजन का ऑक्शन नवंबर में विदेश में हो सकता है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते के में ऑक्शन का आयोजन किया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल की टीमों को इस संभावना के बारे में संकेत दिया है। आईपीएल के सूत्र ने क्रिकबज को बताया, पिछले साल की तरह इस बार भी नीलामी का आयोजन मिडिल ईस्ट में होने की संभावना है। पिछले साल की नीलामी दुबई में हुई थी और अगर इस बार किसी गल्फ सिटी जैसे दोहा या अबू धाबी में आयोजित की जाती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सऊदी अरब, जो हाल ही में क्रिकेट सहित खेलों में भारी निवेश कर रहा है, नीलामी की मेजबानी करने में भी रुचि रखता है। पिछला ऑक्शन दुबई में हुआ था आईपीएल 2024 की नीलामी 23 दिसंबर को दुबई में हुई। ऐसा पहली बार हुआ, जब ढ्ढक्कुका ऑक्शन देश से बाहर हुआ। टीमों के रिटेंशन नियमों का इंतजार आईपीएल की टीमें नीलामी से पहले रिटेंशन नियमों की घोषणा का इंतजार कर रही हैं। बोर्ड ने उन्हें इस घोषणा में देरी के बारे में सूचित किया है। इन नियमों की घोषणा महीने के अंत तक होने की उम्मीद है। राजस्थान रॉयल्स से जुड़ सकते हैं विक्रम राठौर भारतीय टीम में राहुल द्रविड़ के साथ काम कर चुके कोचों के विभिन्न आईपीएल टीमों में शामिल होने की उम्मीद है। भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर को राजस्थान रॉयल्स में द्रविड़ के साथ शामिल होने की संभावना है। द्रविड़ के कार्यकाल में भारत के गेंदबाजी कोच रहे पारस महाम्ब्रे भी लीग में किसी टीम से जुड़ सकते हैं। इन कोचों ने कोचिंग भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए कमेंट्री के प्रस्ताव को ठुकराया था।

स्पाइसजेट-बोर्ड ने 48.7 करोड़ शेयर जारी करने की मंजूरी दी

61.60 प्रति शेयर होगा इश्यू प्राइस, शेयर कैपिटल बढ़कर 1,281 करोड़ हुई

न्यूज क्राइम फाइल

स्पाइसजेट का 16 सितंबर को ओपन हुआ 3,000 करोड़ रुपए का QIP 20 सितंबर को क्लोज हो गया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को 61.60 रुपए प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर 48.7 करोड़ (48,70,12,986) शेयरों का एलोकेशन मंजूर किया है। QIP के लिए फ्लोर प्राइस 64.79 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। अब कंपनी की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़कर 1,281 करोड़ (12,81,68,57,030) रुपए हो गई है, जो पहले 794 करोड़ (7,94,67,27,170) रुपए थी। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स से QIP के जरिए हासिल पैसों का इस्तेमाल कंपनी लेनदारों, पट्टेदारों, वेंडर्स और फाइनेंसर्स का बकाया सेटल करने के लिए करेगी।

स्पाइसजेट के ऊपर 15 सितंबर तक बकाया 601.5 करोड़ रुपए था

स्पाइसजेट के ऊपर 15 सितंबर तक बकाया 601.5 करोड़ रुपए था। कुल राशि में से 297.5 करोड़ रुपए TDS से संबंधित है, 156.4 करोड़ रुपए कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और 145.1 करोड़ रुपए त्रस्ञ्ज से जुड़े हैं।

20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा। जिसमें स्पाइसजेट को 3 एयरक्राफ्ट इंजन का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया गया था। इंजन लीज पर देने वालों यानि लेसर्स को स्पाइसजेट की ओर से भुगतान में चूक के कारण यह निर्देश दिया गया था। 20 सितंबर को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के 11 सितंबर के फैसले के खिलाफ स्पाइसजेट की अपील खारिज कर दी। बेंच ने कहा, हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। यह एक सही आदेश है।

हाई कोर्ट ने 3 एयरक्राफ्ट इंजन का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया था

पहले दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने 14 अगस्त को स्पाइसजेट को 3 एयरक्राफ्ट इंजन का इस्तेमाल 16 अगस्त तक बंद करने और उन्हें लेसर्स- टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस को सौंपने का आदेश दिया था। उसके बाद स्पाइसजेट ने इस आदेश को चुनौती दी और दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दखलंदाजी करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

गिरिडीह (झारखंड) में बाबा झारखंडी नाथ महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर झारखंड वासियों के सुख, समृद्धि और प्रदेश के विकास की प्रार्थना की। महादेव सभी पर अपनी कृपा बनाये रखें।
केंद्रीय गृहमंत्री-अमित शाह

बीजेपी के 50 लाख सदस्य बने

1 करोड़ सदस्य बनाकर यूपी पहले नंबर पर.. मप्र और गुजरात बराबरी पर

न्यूज क्राइम फाइल

तीन सितंबर से शुरू बीजेपी के सदस्यता अभियान में मप्र ने 50 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। एक करोड़ सदस्य बनाकर यूपी देश में पहले नंबर पर है। एमपी और गुजरात 50-50 लाख सदस्य बनाकर बराबरी पर हैं।

बीएल संतोष ने ट्वीट कर दी बधाई

BJP के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ट्वीट कर सदस्यता के आंकड़े साझा किए हैं। संतोष के मुताबिक देशभर में अब तक 4 करोड़ सदस्य बने हैं। इनमें उप्र एक करोड सदस्य बनाकर पहले नंबर पर है। एमपी और गुजरात में 50-50 लाख सदस्य बने हैं। असम में 35 लाख सदस्य बने हैं। संतोष ने सदस्यता के रिकॉर्ड बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है।

वीडी बोले- एमपी सदस्यता में इतिहास बनाएगा

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा- भाजपा के संगठन पर्व के दौरान सदस्यता के मामले में मप्र इतिहास बनाने जा रहा है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार मप्र के बूथ-बूथ के कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत 50 लाख सदस्यता क्रॉस हो गई है। अब तक 57 लाख मिस्ड कॉल हुए है, 50 लाख फार्म भरे जा चुके हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रिकार्ड बनाया है। जो हमारा टारगेट है, उस लक्ष्य से ऊपर सदस्यता होगी।

दो दिन युवाओं की सदस्यता होगी

वीडी शर्मा ने कहा- दो दिनों में माताओं, बहनों की सदस्यता का रिकॉर्ड बना है। 21 और 22 सितंबर को नौजवानों की सदस्यता का दिन होगा। समाज के सभी वर्गों को, अलग-अलग क्षेत्र के लोग बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लोग उत्साह और उमंग के साथ भाजपा के परिवार से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। समाज के हर वर्ग तक भाजपा के कार्यकर्ता और नेतागण पहुंच रहे हैं और लोग मोदी जी को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देकर भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं।

मंत्री विजयवर्गीय की विधानसभा ने सबसे पहले टारगेट क्रॉस किया

सदस्यता अभियान में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र इंदौर क्र.1 ने सबसे पहले टारगेट को क्रॉस किया है। इंदौर क्र.1 में लक्ष्य से ज्यादा 102% सदस्य बने हैं। भोपाल मध्य में 85%, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की विधानसभा मल्हारगढ़ में 84%, इंदौर क्र.2 में 84%, आगर में 79% सदस्यता हुई है।

डीजी जेल ने किया सब जेल का निरीक्षण

न्यूज क्राइम फाइल

भारतीय पुलिस सेवा के महानिदेशक जेल और सुधारात्मक सेवा जीपी सिंह ने शनिवार को निवाड़ी की सब जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल बंदियों के बैरक और रसोई घर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पूरे जेल परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था अच्छी मिली। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक निवाड़ी रायसिंह नरवरिया, शैलेन्द्र सिंह कुशवाह, सहायक जेल अधीक्षक निवाडी और डॉ. आरसी मलाराया, बीएमओ उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान महानिदेशक ने सब जेल के कार्यालय की स्थापना शाखा, वारंट शाखा, ई-प्रिजन, मुलाकात और वीसी आदि व्यवस्था देखी। उन्होंने जेल के अंदर बंदियों के बैरकों और किचन की स्वच्छता देखी। जिसमें साफ-सफाई बहुत अच्छी मिली। जेल में बंदियों को मिलने वाले भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं की पूछताछ की, सभी बंदियों ने जेल प्रशासन की सुविधाओं के प्रति संतोष व्यक्त किया।

फोटो गैलरी

उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी के पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि के मौके पर भोपाल स्थित उनके निवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी एवं भावपुष्प अर्पित किए।

मोदीजी के नेतृत्व में हमारी सरकार जहां पहले ओवर से ही तेजी से रन बना कर देश का स्कोर बढ़ा रही है, वहीं विपक्ष नो बॉल और वाइड बॉल फेंकने में ही देश का बेशकीमती समय और संसाधन बर्बाद कर रहा है।
रक्षा मंत्री-राजनाथ सिंह

4 बड़े शहरों के आरटीओ दफ्तर चला रहे एवजी

किराए के इन कर्मचारियों के पास गोपनीय फाइलों से लेकर सॉफ्टवेयर के पासवर्ड भी

न्यूज क्राइम फाइल

मध्यप्रदेश के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी RTO का सारा कामकाज यहां के कर्मचारी नहीं, बल्कि एवजी संभाल रहे हैं। यानी किराए के कर्मचारी। एवजी यानी ऐसे लोग जिन्हें सरकार ने नियुक्ति नहीं किया, बल्कि आरटीओ के कर्मचारियों ने इन्हें अपना काम करने के लिए तैनात किया है। लगातार तीन दिन तक मध्यप्रदेश के चार बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के आरटीओ में जाकर देखा तो सारा काम ये एवजी करते मिले। भास्कर की टीम ने इन एवजियों की तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद की। एक्सपर्ट का कहना है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना काम करने के लिए किसी दूसरे को नियुक्त नहीं कर सकता। ये नियम के खिलाफ है। इस रिपोर्ट में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर एवजी किस-किस तरह के काम कर रहे हैं। इनकी सैलरी कौन देता है। किस अधिकारी ने कितने एवजी रखे हैं। उनके नाम क्या है और वे किस तरह से पूरा आरटीओ दफ्तर चला रहे हैं।

महिला कर्मचारी मोबाइल पर बात कर रही, एवजी पूरा काम कर रहा

राजधानी भोपाल में आरटीओ का दफ्तर कोकता एरिया में है। अभी नई बिल्डिंग बनी है। यहां अंदर दाखिल होते ही अलग- अलग विभागों की विंडो नजर आती है। लर्निंग लाइसेंस शाखा की विंडो के काउंटर पर दो लोग बैठे हुए हैं। इनमें से एक महिला हैं जिनका नाम रजनी है, जो इस शाखा की बाबू यानी क्लर्क है। दूसरे शख्स का नाम हरि है। हरि जो काम कर

रहा है उसे वो कर ही नहीं सकता। उसे अधिकार भी नहीं है क्योंकि वह आरटीओ का कर्मचारी ही नहीं है। वह एक एवजी है। अपना काम करने के लिए क्लर्क रजनी ने हरि को नियुक्त किया है। हरी की सैलरी भी वो ही देती है।

डेटा एंट्री से लेकर गोपनीय फाइल संभालने का काम कर रहे हैं एवजी

ये केवल एक शाखा का मामला नहीं है। आरटीओ में जिस शाखा में जाएंगे वहां एवजी ही नजर आएंगे। आरटीओ में कर्मचारियों की संख्या महज 34 है, लेकिन आरटीओ से लेकर बाबू तक ने 50 से ज्यादा एवजी तैनात किए हैं। खुद आरटीओ अधिकारी संजय तिवारी ने अपने दफ्तर में 6 एवजी तैनात किए हुए हैं। कई शाखाओं में तो बाबुओं की संख्या से तीन गुना एवजी काम कर रहे हैं। ये एवजी सरकारी फाइलों की प्रक्रिया को पूरा करने से लेकर सॉफ्टवेयर डेटा एंट्री तक का काम संभालते हैं। इनके पास अलग अलग शाखाओं के सॉफ्टवेयर के पासवर्ड तक मौजूद हैं। गोपनीय दस्तावेजों के रख रखाव के साथ ये अपने अफसरों के लिए दलालों से वसूली का काम भी करते हैं।

दलालः दलाल यानी एजेंट, आरटीओ से जुड़े जितने भी काम जैसे लाइसेंस बनवाना, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट दिलाना। ये सभी काम दलाल करते हैं। दलाल इन कामों के एवज में कमीशन लेते हैं। मान लीजिए आपको टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो लाइसेंस प्रक्रिया की फीस 1400 रु. है। यदि यही काम दलाल के जरिए करवाते हैं तो दोगुना पैसा देना पड़ता है। आरटीओ के अलग-अलग कामों के लिए दलालों का कमीशन भी अलग अलग होता है।

एवजी : आरटीओ से जुड़े जो काम दलाल अपने हाथ में लेते हैं उन्हें एवजी पूरा करते हैं। एवजी दफ्तर के भीतर मौजूद होते हैं। वे फाइलों को आगे बढ़ाने और उसे संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का काम करते हैं। दलाल आम आदमी से जो कमीशन लेता है उसका एक हिस्सा अधिकारी का भी होता है। अधिकारी इसी हिस्से में से कुछ राशि एवजी को देता है।

आरटीओ के पास 6, दूसरे नंबर पर है ट्रांसफर- टैक्स समायोजन शाखा

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यानी आरटीओ के ऑफिस में 6 एवजी काम करते हैं। सभी शाखाओं से जुड़े काम आखिर में आरटीओ के पास आते हैं। यहां सभी काम एवजी के जरिए ही होते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा एवजी वाहन ट्रांसफर और टैक्स समायोजन शाखा में है। यहां इनकी संख्या 5 हैं। इस शाखा में अन्य राज्यों के वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट, नाम परिवर्तन, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस अपडेट, ट्रैवल लाइसेंस, पीयूसी लाइसेंस जैसे काम किए जाते हैं। इन सभी कामों को एवजी ही पूरा करते हैं।

महिला कर्मचारी भी एवजी तैनात करने में पीछे नहीं

आरटीओ में महिला कर्मचारियों की संख्या 12 हैं। और इन्होंने अपना काम करने के लिए 22 एवजियों को तैनात किया हुआ है। ज्यादातर महिला कर्मचारी लाइसेंस ट्रांसफर, न्यू रजिस्ट्रेशन और वाहन ट्रांसफर शाखा में तैनात है। यहां विंडो से जमा होने वाली फाइल लेने से लेकर टीप लगाने तक का काम और डेटा सॉफ्टवेयर में अपलोड करने का काम भी एवजी ही करते हैं।

भोपाल के गैस राहत अस्पतालों में सेवा देंगे 15 डॉक्टर्स

2 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ; जीएमसी में पीजी की नौ सीटें मंजूर

न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल के गैस राहत अस्पतालों में 15 डॉक्टर्स सेवाएं देंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इन डॉक्टर्स को 2 साल की प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए अस्पतालों में पदस्थ किया है। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। डॉक्टर्स में एक मेडिकल विशेषज्ञ, एक सर्जिकल विशेषज्ञ, एक अस्थि रोग विशेषज्ञ, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक निश्चेतना विशेषज्ञ और 10 चिकित्सा अधिकारी हैं। उधर जीएमसी में नौ पीजी सीटों को मंजूरी दी गई है।

यहां पदस्थ किए गए डॉक्टर्स

इन 15 डॉक्टर्स में से मेडिकल विशेषज्ञ ने जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में, सर्जिकल विशेषज्ञ एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ ने जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में कार्यभार संभाल लिया। कमला नेहरू अस्पताल में दो चिकित्सा अधिकारियों ने ज्वाइन किया। जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, शाकिर अली खान अस्पताल एवं रसूल अहमद सिद्धिकी पल्मोनरी मेडिसिन सेंटर में एक-एक चिकित्सा अधिकारी ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया।

डॉक्टर्स के लिए लिखा था पत्र

बता दें कि गैस राहत अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सा अधिकारियों की पदपूर्ति करने के लिए भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर चिकित्सकों की सेवाएं लेने का मांग पत्र भेजा था। स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना की मांग मानकर 15 डॉक्टर्स की गैस राहत अस्पतालों में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने के आदेश जारी कर दिए हैं।

जीएमसी में पीजी की नौ सीटों को मंजूरी

उधर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) नई दिल्ली द्वारा गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के एनाटॉमी विभाग में 9 अतिरिक्त स्नातकोत्तर (पी.जी.) सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस वृद्धि के साथ पीजी सीटों की संख्या 2 से बढ़कर 11 हो गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने डीन जीएमसी डॉ कविता सिंह एवं गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि से राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

ओडिशा में घटित भयंकर घटना ने देश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस से मदद मांगने गए एक सेना अधिकारी को बेरहमी से पीटा गया और उनकी मंगेतर को कस्टडी में उत्पीड़ित किया गया।
नेता प्रतिपक्ष-राहुल गांधी

भोपाल में साइबर ठगों को खाता बेचने वाले पांच गिरफ्तार

शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी के बाद आरोपियों के दिए खातों में जाती थी रकम

न्यूज क्राइम फाइल

शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर 9.35 लाख रुपए की ठगी करने वाले की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को खाता बेचने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कोझिकोड केरल और भुसावल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पांचो आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मोहम्मद जैनुल निवासी कोहेफिजा ने सायबर क्राइम में लिखित शिकायत आवेदन दिया था। इसमें बताया था कि करन बिरला नाम के व्यक्ति द्वारा वॉट्सऐप पर पर संपर्क कर PMHD-FC नाम के एपलीकेशन के माध्यम से शेयर मार्केट में सहाज सोलार नाम की कंपनी में इनवेस्ट करने का झांसा दिया। आरोपी के झांसे में आकर विभिन्न बैंक खातो में पैसा आनलाइन ट्रांसफर किया था। करीब 11 बार में 9.35 लाख रुपए आरोपियों ने ठग लिया। शुरुआत में जब छोटे इंवेस्टमेंट किए तो आरोपियों ने मुनाफा सहित रिटर्न किया था। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते ही आरोपियों ने हर तरह का संपर्क खत्म कर दिया।

जानिए कौन हैं आरोपी

■रियाज पिता शरीफ निवासी बडकरा जिला कोझिकोड केरल 12 वीं कक्षा तक पढ़ा है। स्वयं के नाम पर फर्जी खाते खुलवाकर पैसे लेकर बेचने का काम करता है।

■रसल पिता इब्राहिम निवासी कुट्टीयाडी जिला कोझिकोड केरल 12 वीं कक्षा पास है। फर्जी खाते खरीदकर आरोपी मोहम्मद मुबाशिर को पैसे लेकर बेचने का काम करता है।

■सचु पिता वासु निवासी नाडापुरम जिला कोझिकोड केरल बी.कॉम ग्रेजुऐट है। स्वयं के नाम पर फर्जी खाते खुलवाकर पैसे लेकर बेचने का काम करता है।

■मोहम्मद मुबाशिर पिता असरफ निवासी कुट्टीयाडी जिला कोझिकोड केरल 12वीं पास है। फर्जी खाते खरीदकर अन्य साइबर जालसाजों को बेचने का काम करता था।

■राकेश जाधव पिता नामोद जाधव निवासी भुसावल महाराष्ट्र 12वीं पास है। फर्जी खाते आरोपी आकाश चनाडे से खरीदकर अन्य आरोपियों को पैसे लेकर बेचने का काम करता है।

वनरक्षकों के वेतन में गड़बड़ी, वन-वित्त बराबर के जिम्मेदार

वेतनमान निर्धारण की नोटशीट ने 4 साल में तय किया 300 मीटर का सफर

न्यूज क्राइम फाइल

मध्य प्रदेश के 6592 वनरक्षकों के वेतन निर्धारण में गलती के लिए वन एवं वित्त विभाग के अधिकारी बराबर के जिम्मेदार हैं। जहां वन विभाग ने वेतन निर्धारण और वित्त विभाग से उसके अनुमोदन में 9 साल लगा दिए, तो वहीं साल 2009 से 2011 तक वनरक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं के परीक्षण के दौरान जिला कोषालय अधिकारियों ने इसी वेतन निर्धारण को सही ठहराया है और अब वही गलत हो गया। सबसे पहले मामला तब सामने आया जब वर्ष 2016 में सातवें वेतनमान का निर्धारण हुआ और 2018 में दोबारा सेवा पुस्तिकाएं कोषालय पहुंचीं। तब भोपाल और नर्मदापुरम (होशंगाबाद) के जिला कोषालय अधिकारियों ने इस वेतन निर्धारण पर आपत्ति ली। बता दें कि 6592 वनरक्षकों को जनवरी 2006 से 2014 के बीच 5200 के स्थान पर 5680 वेतन बैंड दिया गया। यानी हर माह 480 रुपए अधिक और अब उनसे 165 करोड़ रुपए की वसूली करने की तैयारी है।

प्रदेश में 1 जनवरी 2006 से 6वां वेतनमान लागू हुआ है। जिसमें प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित वनरक्षकों का वेतनमान एक (5200+1800) कर दिया गया। 28 फरवरी 2009 को वित्त विभाग ने सभी विभागों को लिखा कि विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार संवर्गवार वेतनमान का निर्धारण कर लें। इस काम में वन विभाग को 5 साल 7 महीने लग गए। विभाग ने 8 सितंबर 2014 को वेतनमान में संशोधन की अधिसूचना प्रकाशित की, पर इसमें भी यह नहीं लिखा कि यह कब से लागू होगा। अब संवर्गवार वेतनमान का अनुमोदन वित्त विभाग से कराना था। तब वन बल प्रमुख कार्यालय सतपुड़ा भवन में संचालित होता था, जिसकी मंत्रालय से 300 मीटर से भी कम दूरी है। इतनी दूरी तय करने में वेतनमान संशोधन की नोटशीट को 4 साल लग गए। वित्त ने वेतनमान का अनुमोदन 14 सितंबर 2018 को किया। तब भी इसे लागू करने की तारीख नहीं लिखी गई। उल्लेखनीय है कि 5वें वेतनमान तक वनरक्षकों को दो वेतनमान दिए जाते थे। अप्रशिक्षित वनरक्षकों को 2750 और प्रशिक्षित को 3050 रुपए। 6वें वेतनमान में दूसरा वेतन बैंड विलोपित कर दिया गया, जबकि कर्मचारी प्रशिक्षित वनरक्षकों के लिए 5680 वेतन बैंड की मांग कर रहे थे। जब उन्हें 1900 ग्रेड-पे दे दिया, तो 5680 वेतन बैंड का निर्धारण कर दिया गया, क्योंकि 1900 ग्रेड-पे इसी वेतन बैंड में दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ ने सुलझा लिया मामला

मध्य प्रदेश से वर्ष 2000 में अलग हुए छत्तीसगढ़ राज्य में भी यही गड़बड़ी वनरक्षकों के वेतनमान में हुई थी। जिसे पिछले साल हल कर लिया गया। 6 जुलाई 2023 की कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को लाया गया और कैबिनेट ने विभागीय सेटअप स्वीकृति दिनांक 26 मार्च 2003 के बाद से नियुक्त सभी वनरक्षकों का वेतनमान एक समान मान्य कर लिया। जिसके आदेश 20 जुलाई 2023 को जारी कर दिए गए।

यह हो सकता है विकल्प

मध्य प्रदेश का मामला निपटाने के लिए एक ही विकल्प है। डॉ. मोहन कैबिनेट छत्तीसगढ़ सरकार की तरह निर्णय लेते हुए इस वेतनमान को 1 जनवरी 2006 से लागू कर दे। इससे भोपाल और नर्मदापुरम वनवृत्त में पहले और बाद की भर्ती के बीच वेतन की विसंगति भी दूर होगी।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी के पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि के मौके पर भोपाल स्थित उनके निवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी एवं भावपुष्प अर्पित किए।
डिप्टी सीएम मप्र- जगदीश देवड़ा

शिवराज, वीडी शर्मा के खिलाफ हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

फैसला सुरक्षित, कपिल सिब्बल ने विवेक तन्खा का रखा पक्ष, बोले- अधिवक्ता पर लांछन लगाना गलत

वीडी शर्मा | भूपेंद्र सिंह | शिवराज सिंह चौहान

न्यूज क्राइम फाइल

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जबलपुर पहुंचे। बता दे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी किया गया था। उसी को चुनौती देते हुए शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा, पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह पर किए गए 10 करोड़ के आपराधिक मानहानि केस में शनिवार को हाईकोर्ट में दो घंटे तक सुनवाई चली। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का पक्ष रखने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि अगर कोर्ट के बाहर किसी अधिवक्ता के ऊपर गलत लांछन लगाया जाए तो यह गलत है। पूरी सुनवाई के दौरान राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा भी कपिल सिब्बल के साथ मौजूद रहे। हाईकोर्ट में बहस कर अदालत से बाहर आए कपिल सिब्बल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जो वकील है, कोर्ट में जाकर कर्तव्य निभाते है। बहस करते है और कोर्ट के बाहर अगर लांछन लगे जो कि लगाने वाले को भी पता है कि झूठ है और प्रोफेसन पर अगर चोट लगे तो मैं समझता हूं कि समाज के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि एक वकील तो अपना काम करता है। उस आधार पर ही न्याय कोर्ट से मिलता है। अगर उन पर ही गलत आरोप लगाया जाए तो न्याय की व्यवस्था क्या रहेगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि शिवराज सिंह जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके है। उन्हें 19 तारीख को नोटिस दिया और बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में हमने ओबीसी का मुद्दा हमारे पास नहीं था, जो आरोप आप लगा रहे है। 21 दिसंबर को विवेक तन्खा ने पत्रकार वार्ता कर उनके आरोप को झूठा बताया तब भी कोई जवाब नहीं आया। कपिल सिब्बल ने कहा कि जो राजनेता लोग ऐसा करेंगे तो वकील इकट्ठा होंगे तो उन्हें सामना करना ही पड़ेगा, जिसकी शुरुआत विवेक तन्खा ने कर दी है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल के साथ मौजूद रहे। विवेक तन्खा ने कहा कि मैं आज की सुनवाई से पूरी तरह से संतुष्ट हूं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कानून की जो परिभाषा कोर्ट में रखी वह सही है। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के पद पर भी रह चुका हूं और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ता हूं। विवेक तन्खा ने कहा कि यह मानहानि का मुकदमा एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक अधिवक्ता के रूप में मैंने दायर किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को कोर्ट की कार्रवाई के विषय में झूठ मत बोलो, उनके साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि यह एक सीरियल मामला है,

जिस पर पूरे देश की निगाह रहती है। विवेक तन्खा ने यह भी कहा कि कोर्ट और वकीलों के साथ खिलवाड़ करना गलत है, इसको लेकर बहस हुई है। विवेक तन्खा ने अदालत से उम्मीद कि है फैसले के जरिए एक नजीर पेश की जाए। बहरहाल जल्द ही इस मामले पर फैसला आएगा। हाईकोर्ट ने वारंट पर रोक लगा दी थी। राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी तो उक्त भाजपा नेताओं ने साजिश करते हुए इसे गलत ढंग से पेश किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने जिस तरह से गलत बयान देकर ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठीकरा विवेक तन्खा के सिर पर फोड़ दिया था और उनकी छवि व अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया था, उसी को लेकर विवेक तन्खा ने एमपी-एमएलए कोर्ट में तीनों के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका के मुताबिक अपने खिलाफ गलत बयानबाजी को लेकर राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा था। विवेक तन्खा का कहना था कि यह बयान पूरी तरह गलत था और इससे उनकी मानहानि हुई है. इसलिए इन तीनों नेताओं के खिलाफ उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में आपराधिक अवमानना का मुकदमा दर्ज करवाया था।

सेंट्रल जेल में कीलें लेकर एक-दूसरे पर टूट पड़े कैदी

10 मिनट तक मारपीट हुई; दोनों कुख्यात बदमाश, हत्या-हत्या के प्रयास में बंद

न्यूज क्राइम फाइल

जबलपुर केंद्रीय जेल में रविवार दोपहर दो कैदियों में मारपीट हो गई। दोनों ने जेल में पड़ी कील उठा लीं और एक-दूसरे पर टूट पड़े। 10 मिनट तक दोनों गुत्थमगुत्था होते रहे। बड़ी मुश्किल से जेल प्रहरियों ने दोनों को अलग किया। जेल प्रशासन ने दोनों का इलाज कराने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों ही शहर के कुख्यात बदमाश हैं, नाम अनुज और सुमित हैं। हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध वसूली के अपराध में सजा काट रहे हैं।

दोनों को अलग बैरक में रखा गया

अनुज खटीक और सुमित केवट के बीच जब मारपीट हो रही थी, तब उन्हें उनके साथी भी अलग करने की कोशिश में थे। वे समझा रहे थे, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थे। घटना में दोनों को मामूली चोट आई है। जानकारी लगते ही जेल अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और दोनों को इलाज करवाने के बाद जेल नियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। विवाद के बाद दोनों को अलग-अलग बैरक में रखा गया है। जेल अधीक्षक का कहना है कि दोनों ही आदतन बदमाश हैं। यह भी जांच की जा रही है कि इनके पास लोहे की कील कैसे आई।

मां से हमारा अस्तित्व है, मां जीवन का आधार है। आज मेरी मां के श्राद्ध का दिन है। मैं भोपाल में हर वर्ष पूरे परिवार के साथ मां का श्राद्ध करता रहा हूं।
शिवराज सिंह चौहान-केंद्रीय कृषि मंत्री

आतिशी दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बनीं

शपथ के बाद केजरीवाल के पैर छुए; कैबिनेट में 5 मंत्री

संदीप कुमार सिंह

अरविंद केजरीवाल के शीर्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी ने शनिवार को राज निवास में एक समारोह के दौरान अपने नए मंत्रिपरिषद के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पार्टी द्वारा घोषित नई मंत्रिपरिषद में नए शामिल हुए सुल्तानपुर माजरा विधायक मुकेश अहलावत के अलावा मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन शामिल हैं। आतिशी के सौरभ भारद्वाज ने मंत्री पद की शपथ ली। आतिशी दिवंगत सुषमा स्वराज और दिवंगत शीला दीक्षित के बाद देश की 17वीं और राष्ट्रीय राजधानी की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनीं। राय, गहलोत, भारद्वाज और हुसैन निवर्तमान केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे हैं। आतिशी सरकार का कार्यकाल संक्षिप्त होगा क्योंकि दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी (आप) ने एक अहम मोड़ पर आतिशी को शीर्ष पद प्रदान किया है, क्योंकि पार्टी अगले साल की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव में ना केवल सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है, बल्कि वह चाहती है कि दिल्ली सरकार जन कल्याण से जुड़े लंबित नीतियों और योजनाओं पर तेजी से काम करे। यह वजह है कि आतिशी को पद संभालने के बाद कड़ी मेहनत करनी होगी और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 और दहलीज पर सेवाओं की डिलीवरी जैसी अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तेज गति से काम करना होगा। सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन के इस्तीफे के बाद आतिशी, सौरभ भारद्वाज के साथ दिल्ली सरकार में शामिल हो गईं। आतिशी (43)ने केजरीवाल सरकार में वित्त, राजस्व, शिक्षा और लोक निर्माण विभाग सहित 13 प्रमुख विभागों का नेतृत्व करते हुए शामिल हुईं।

कोलकाता रेप-मर्डर

जूनियर डॉक्टर्स का 41 दिन बाद धरना खत्म

न्यूज क्राइम फाइल

बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने 41 दिन लंबी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। यह विरोध प्रदर्शन एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद शुरू हुआ था। शनिवार से डॉक्टर आवश्यक सेवाएं फिर से शुरू करेंगे, लेकिन OPD और चुनी हुई सर्जरी में शामिल नहीं होंगे। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक राज्य सरकार सुरक्षा के मुद्दे पर आश्वासन नहीं देती, तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। डॉक्टरों की यह घोषणा राज्य सरकार द्वारा अधिकांश मांगों को मानने के बाद आई है।

सुरक्षा के मुद्दे पर डॉक्टरों की शर्त

डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि वे केवल आंशिक रूप से काम पर लौट रहे हैं। वे तब तक OPD सेवाओं और चुनी हुई सर्जरी में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक राज्य सरकार सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती। डॉक्टरों की मांग है कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए

ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस विरोध के दौरान राज्य सरकार ने ज्यादातर मांगों को स्वीकार किया है, जिसमें अस्पतालों में सुरक्षा के नए उपाय शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने उठाए सुरक्षा के कदम

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया है। हालांकि, खुद मुख्यमंत्री ने अंतिम बैठक में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि मुख्य सचिव ने डॉक्टरों के साथ मुलाकात की। उन्होंने सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें ड्यूटी रूम्स, सीसीटीवी, और महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती शामिल है। इसके अलावा, अस्पतालों में रात में निगरानी के लिए मोबाइल पुलिस टीमें तैनात की जाएंगी।

डॉक्टरों का विरोध खत्म नहीं, कानूनी लड़ाई जारी

डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि यह आंशिक वापसी है और आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा के मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वे फिर से कार्यविराम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा, डॉक्टरों ने इस केस को लेकर कानूनी लड़ाई जारी रखने का भी ऐलान किया है। डॉक्टरों की मांग है कि 31 वर्षीय डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले।

प्रदर्शन से लेकर पुलिस जांच तक विवाद

31 वर्षीय डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के बाद कोलकाता के ऋन्न चढ्ढ्ह मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। इस मामले में मुख्य संदिग्ध कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर है। पुलिस जांच में देरी और परिवार की इच्छा के खिलाफ अंतिम संस्कार ने विवाद को और बढ़ा दिया। विरोध प्रदर्शन ने राज्य सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया।

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक उदय प्रताप सिंह चौहान द्वारा कविता ऑफसेट प्रिंटर्स, एमपी नगर जोन -1 भोपाल (म. प्र.) से मुद्रित एवं 1209 पुष्पा नगर चांदबड़, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- उदय प्रताप सिंह चौहान, मो.7223003441 (प्रति सोमवार को प्रकाशित) समाचारों से संपादक का सहमत होना जरूरी नहीं। (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।) RNI.NO MPHIN/2015/63623